

ई-वेस्ट खत्म करने को पायलट प्रोजेक्ट बनाएगी सरकार

आमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश और विशेष तौर से राजधानी में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ पायलट प्रोजेक्ट बनाएगी। यह जानकारी उप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त निदेशक डॉ. एसके श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने वित्तीय मदद का भरोसा भी दिया। कहा कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इसका समाधान निकालना होगा। वे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, परिषद उसमें पूरी मदद देगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर आयोजित गोष्ठी में शनिवार को विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के निस्तारण



रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर भवन में शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए हुई संगोष्ठी में शामिल विशेषज्ञ। आमर उजाला

पर काम कर रहे आरएन भार्गव ने कहा, प्लास्टिक के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा नई मुसीबत बन चुका है। बेकार हो चुके कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, सीएफएल, पेंसिल बैट्री सेल, मोबाइल फोन करीब 70 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा अन्य टेलीकॉम उपकरण, मेडिकल उपकरण,

बिजली व घरेलू उपकरण भी इस कचरे को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में हर साल 17 लाख टन ई-वेस्ट पैदा हो रहा है, जिसमें से 3.5 टन यूपी का हिस्सा होता है। इस वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, मिट्टी जहरीली हो रही है और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने इस कचरे की री-साइकलिंग

इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर गोष्ठी में बोले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त निदेशक

के लिए प्रभावी सिस्टम बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया जहां करीब एक लाख नागरिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस कचरे से चांदी, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम जैसे धातु री-साइकिल किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में डॉ. एन पाणिग्रही, हर्षिता मेहता, नूपुर मित्तल, डॉ. पारुल वर्मा, डॉ. रंजना रजनीश, डॉ. धनंजय सिंह, आदि ने भी अपने शोध पत्र साझा किए। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉ. भरतराज सिंह व मानद सचिव आरके त्रिवेदी ने अतिथियों का अभिनंदन किया।